

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेल्कम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 205

सोमवार, 03 अगस्त-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

पीएम मोदी ने शुरू किया ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’, 1 करोड़ युवाओं ने ली शपथ



वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉल के जरिए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद देश के युवाओं



को नशे के खिलाफ एक साथ लाना है, ताकि भारत को नशा मुक्त बनाया जा सके और देश तरक्की कर सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना और सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने

कहा, ‘आप सभी इस बड़े अभियान के लीडर हैं और आपने मेरे भरोसे को और मजबूत किया है।’ पीएम मोदी ने युवाओं से आगे आकर इस अभियान से जुड़ने और अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की।

हर रविवार होंगे जागरूकता के काम

सरकार की योजना के मुताबिक, इस अभियान के तहत हर रविवार पूरे देश में अलग-अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इनमें खेल, पैदल यात्रा, योग, नाटक, रैली और चित्र बनाने जैसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी।

अच्छा काम करने वालों को मिलेगा सम्मान

इस अभियान में बेहतरीन काम करने वाले युवाओं और संस्थाओं को 50वें, 75वें और 100वें हफ्ते में सम्मानित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि नशा मुक्त युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस अभियान का मकसद युवाओं को सेहतमंद और जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

10 हजार जगह कार्यक्रम, 1 करोड़ युवाओं ने ली कसम

यह अभियान आम लोगों और युवाओं के जुड़ने से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत में देश भर में करीब 10,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम हुए, जहां 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा युवाओं ने नशा न करने की कसम खाई।

राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे पर खुद को बताया छात्र, युवाओं के लिए साझा किया खास संदेश

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क



नई दिल्ली। फ्रेंडशिप डे के मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के युवाओं के लिए एक खास मैसेज शेयर किया। उन्होंने सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं दीं और लिखा कि वह आज भी खुद को एक छात्र ही मानते हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने दोस्ती को जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता बताते हुए कहा कि प्यार, भरोसा और एक-दूसरे से सीखते रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘अभी भी एक विद्यार्थी हूं, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। आज का

सबक आज मित्रता दिवस है। सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार।’ आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई

सरकार युवाओं को डरा नहीं सकती

इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये दोनों देश के युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये नेता भारत का बीता हुआ कल हैं और उन्हें सोचना चाहिए कि वे देश के आने वाले भविष्य के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं।

छात्रों और युवाओं से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी थीं। कांग्रेस नेता ने देश भर में कई युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराए जाने के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार हंगामा और धक्का-मुक्की, सांसद ने लगाए हत्या की साजिश के आरोप

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी दौरान बवाल और उनके साथ धक्का-मुक्की की खबर सामने आ रही है। यह मामला तब बढ़ा जब सांसद पप्पू यादव दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवा पहनने के विवाद पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान एक शख्स ने पूछा कि आप भगवा पहनकर भगवान राम की तस्वीर अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के सामने रख रहे हैं ये कैसा सम्मान है। इसी दौरान पप्पू यादव के साथ समर्थकों ने उसे शख्स को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।



मुझ पर चाकू से हमला करने आया था: पप्पू यादव

इस घटना को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने कहा, ‘व्या कोई मुझ पर हमला करने के लिए मेरे घर में घुस सकता है? वह मुझ पर चाकू से हमला करने आया था।’ वहीं उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ‘वह व्यक्ति हमला कर रहा था और फिर भी दिल्ली पुलिस उसे बचा रही थी।’

जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें जनप्रतिनिधि: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में सर्वदलीय बैठक को किया संबोधित

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों (विधानसभा/विधान परिषद सदस्यों) से कहा कि जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें। साथ ही स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री रविवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक 3 अगस्त (सोमवार) से शुरू हो रहे



विधानसभा के मानसून सत्र के संचालन के संबंध में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदन जनप्रतिनिधियों को संवाद करने का मंच प्रदान करता है। इससे निकले परिणाम जनोपयोगी होते हैं। 9 वर्ष में विधानसभा ने पूरे देश में संसदीय कार्यप्रणाली में उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है।

सदन स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा के लिए जाना जा रहा है। यह काम सभी दलों के नेताओं की वजह से संभव हुआ है। बैठक में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानसून सत्र में आमजन से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि को जनता के हित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में गंभीरता से उठाना चाहिए। सीएम ने सभी सदस्यों से अपील की कि सदन



के सुचारु संचालन में सभी सदस्यों का सहयोग मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त/संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री

डॉ. संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’, निषाद पार्टी विधानमंडल दल के नेता रमेश सिंह, अपना दल (एस) के आरके पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल बालियान आदि मौजूद रहे।

सावन के पहले सोमवार पर दूधेश्वरनाथ मंदिर में होगी शिव भक्ति और आस्था की अमृत वर्षा

आठों पहर के पूजन, रुद्राभिषेक और भगवान के दिव्य श्रृंगार की विशेष व्यवस्था



वेल्कम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। सिद्धपीठ कांवड़दूधेश्वरनाथ मठ महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर भक्ति, आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मंदिर के पीठाधीश्वर, जना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष तथा हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज के पावन सान्निध्य और अध्यक्षता में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।

श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज ने बताया कि सावन के पहले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग, आयुष्मान योग, सुकर्मा योग और शिव योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि प्रीति योग प्रेम और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, जबकि आयुष्मान योग दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करता है। सुकर्मा योग शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और शिव योग में की गई साधना का विशेष महत्व बताया गया है।

मंदिर के मीडिया प्रभारी एस.आर. सुथार ने बताया कि भगवान दूधेश्वर के जलाभिषेक का क्रम रविवार की रात्रि 12 बजे से शुरू होकर सोमवार की रात्रि 12 बजे तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान मंदिर के कपाट चौबीसों घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। रात्रि दो बजे भगवान दूधेश्वर का भव्य श्रृंगार किया जाएगा।

आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर मायावती की बड़ी कार्रवाई, बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी में अनुशासन तोड़ने के आरोप में उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के ससुर हैं।

दूसरे राज्यों में भी सही से नहीं किया काम

मायावती ने आगे लिखा कि इसके



बावजूद अशोक सिद्धार्थ ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लगातार उनके खिलाफ शिकायतें आती रहें। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी जब उन्होंने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया, तो उन्हें सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था।

पहले भी मिली थी माफी, फिर दोहराई वही गलती

मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव के दौरान पार्टी टिकट के बंटवारे में मनमानी और नियम तोड़ने की वजह से अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया था। हालांकि, बाद में इस शर्त पर उन्हें वापस लिया गया था कि वे ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उन्हें यूपी से दूर रखकर सिर्फ दूसरे राज्यों में पार्टी का काम संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी।

गया था।

अफवाह फैलाने पर मायावती सख्त, हमेशा के लिए रास्ता बंद

मायावती ने कहा कि इसके बाद भी यूपी की राजनीति में उनकी वापसी को लेकर जानबूझकर गलतफहमी फैलाई

जा रही थी। यह सब आने वाले यूपी चुनाव के लिए चलाए जा रहे अभियान को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। इसलिए पार्टी के हित में अशोक सिद्धार्थ को तुरंत प्रभाव से बाहर कर दिया गया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें आगे कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।

‘चार दिन की बची है भाजपा सरकार, इसलिए 4 दिन का बुलाया विशेष सत्र’, अखिलेश ने योगी सरकार पर कसा तंज

वेल्कम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (3 अगस्त 2026) से शुरू होने जा रहा है। चार दिन के इस विशेष सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सरकार बस चार दिन की ही बची है इसलिए विधानसभा का सत्र भी चार दिन का ही हो रहा है। सपा प्रमुख ने चार दिन के विशेष सत्र का पूरा कार्यक्रम भी पर शेयर किया है।

चार दिन विधानसभा में क्या-क्या होगा?

अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यूपी विधानसभा के चार दिन के सत्र का पहला दिन श्रद्धांजलि में निकाल दिया जाएगा, दूसरे दिन अयोध्या के प्रभु राम जी के मंदिर में हुई सुनियोजित चोरी के महापाप की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी जाएगी जबकि तीसरे दिन प्रयागराज जैसे पूरे प्रदेश में हुए छात्र आंदोलन से बचने में निकाल देगी। चौथे दिन दुखी मां के संराम अपमान पर मुंह छिपाकर जल्दी से सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकाल देगी।

‘बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी’

अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि



भाजपा को यह मालूम हो चुका है कि वह कभी सरकार में वापस नहीं आएगी, विधानसभा को महत्व नहीं दे रहे हैं बस सत्र आयोजित करने की

औपचारिकता निभा रहे हैं। भाजपा की चला-चली की बेला का मानसून सत्र भी चला-चली टाइप का सत्र है। अब भाजपा जाएगी, फिर कभी न आएगी!

मानसून सत्र में क्या-क्या हो सकता है?

बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक आयोजित होगा। इससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जो विधान भवन में होगी। इस बैठक से पहले ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट, विधेयक और अन्य जरूरी मामलों पर चर्चा होने की संभावना है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा संभव

विधानसभा के इस सत्र में जहां विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है तो वहीं योगी सरकार अपने 10 साल के कामकाज को बताएगी। यूपी विधानसभा सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे जरूरी मुद्दों को लेकर हंगामा होने की संभावना है। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। 5 अगस्त को विधायी कार्य और अन्य जरूरी सरकारी कामकाज किए जा सकते हैं और 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और कामकाज खत्म होगा।

संपादक की कलम से

पीओके की पुकार और दुनिया की जिम्मेदारी

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, वे केवल एक चुनावी प्रक्रिया की कहानी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनविश्वास के गहरे संकट की दारस्तान हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति निष्पक्ष चुनाव, नागरिक स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही में निहित होती है, लेकिन जब चुनाव भय, हिंसा, प्रशासनिक दबाव और घाथेली के आरोपों से घिर जायें, तब लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाता है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति इसी कठोर वास्तविकता की ओर संकेत करती है। वहाँ के लोगों का आक्रोश केवल चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों की अन्वदेखी के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि वहाँ का असंतोष अब स्थानीय मुद्दा न रहकर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है।



ललित शर्मा
संपादक

लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। यदि किसी क्षेत्र में चुनाव पहले से तय परिणामों का माध्यम बन जायें, यदि सत्ता का पूरा तंत्र एक दल विशेष के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, यदि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता का प्रभाव प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जनता के मन में यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि उसका मत परिवर्तन ला सकता है, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है। पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार-बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी या द्वावस्था विरोधी बताकर दबाने का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्ववसनीयता स्वतः समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उसके लोकतांत्रिक दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद वहाँ का सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, महँगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि

देश में उपजा कुविचार

उदय कशोर साह

कविता



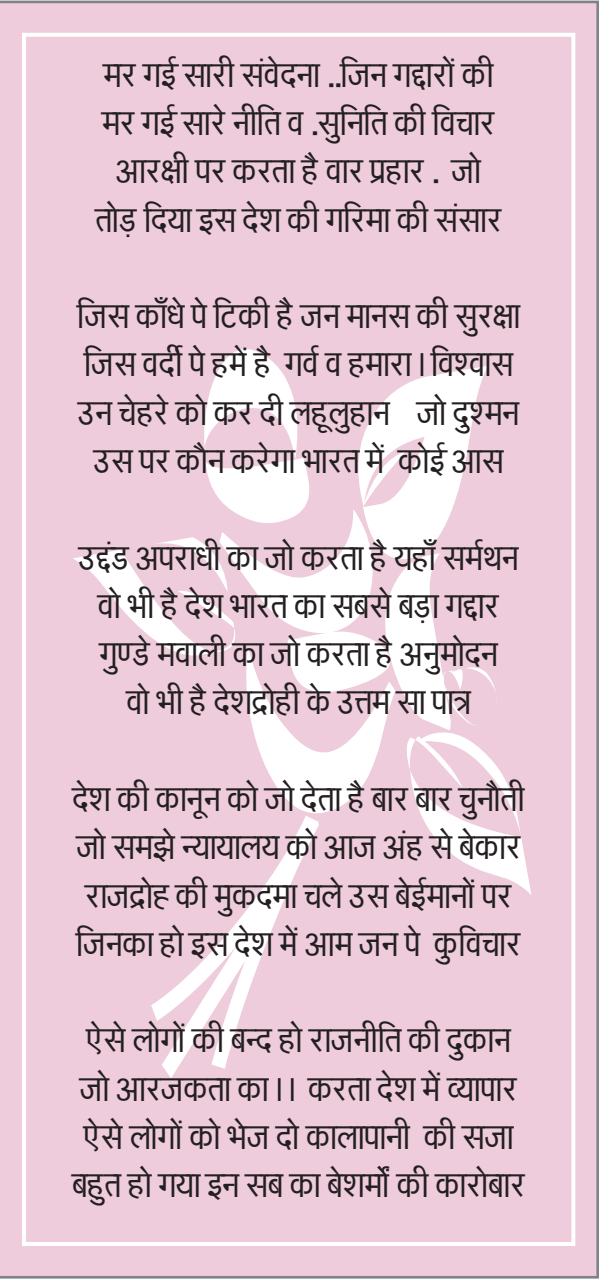
मर गई सारी संवेदना ..जिन गद्दारों की मर गई सारे नीति व .सुनिति की विचार आरक्षी पर करता है वार प्रहार . जो तोड़ दिया इस देश की गरिमा की संसार

जिस काँधे पे टिकी है जन मानस की सुरक्षा जिस वर्दी पे हमें है गर्व व हमारा। विश्वास उन चेहरे को कर दी लहलुहान जो दुश्मन उस पर कौन करेगा भारत में कोई आस

उड़्ड अपराधी का जो करता है यहाँ समर्थन वो भी है देश भारत का सबसे बड़ा गद्दार गुण्डे मवाली का जो करता है अनुमोदन वो भी है देशद्रोही के उत्तम सा पात्र

देश की कानून को जो देता है बार बार चुनौती जो समझे न्यायालय को आज अंह से बैकार राजद्रोह की मुकदमा चले उस बेईमानों पर जिनका हो इस देश में आम जन पे कुविचार

ऐसे लोगों की बन्द हो राजनीति की दुकान जो आरजकता का ।। करता देश में व्यापार ऐसे लोगों को भेज दो कालापानी की सजा बहुत हो गया इन सब का बेशर्मा की कारोबार



स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित करारक ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी. सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया। संपादक : ललित शर्मा सम्पर्क सूत्र: 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

संपादकीय

आर्थिक सहायता तक सीमित हो आरक्षण, अन्य सभी आरक्षण राष्ट्र की प्रगति में अभिशाप!



एनके शर्मा
लेखक

आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो, सहायता का वास्तविक पात्र है। उनका कहना है कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती; भूख का कोई धर्म नहीं होता; अभाव किसी वंश का परिचय नहीं पूछता। ऐसे में यदि किसी निर्धन विद्यार्थी को केवल उसकी जाति के कारण सहायता न मिले, जबकि एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति केवल आरक्षण श्रेणी के आधार पर लाभ प्राप्त कर ले, तो यह व्यवस्था न्याय के बजाय असंतोष को जन्म दे सकती है। यह भी कहा जाता है कि स्वतंत्रता के दशकों बाद भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा का विस्तार, शहरीकरण, संवैधानिक अधिकार, न्यायपालिका की सक्रियता तथा अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने समाज की संरचना में बदलाव लाया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, यदि नीतियों की समय-समय पर समीक्षा न हो, तो वे अपने मूल उद्देश्य से भटक सकती हैं। किसी भी लोकतंत्र में नीति का मूल्यांकन उसके परिणामों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर। दूसरी ओर, आरक्षण के वर्तमान स्वरूप के समर्थक यह कहते हैं कि भारत में सामाजिक भेदभाव और संरचनात्मक असमानताएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। उनका तर्क है कि केवल आर्थिक स्थिति सामाजिक बहिष्कार, ऐतिहासिक वंचना और अवसरों की पीढ़ीगत कमी की भरपाई नहीं कर सकती। इसलिए उनके अनुसार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को

भारत में आरक्षण का प्रश्न केवल संवैधानिक व्यवस्था का विषय नहीं है; यह सामाजिक न्याय, समान अवसर, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विमर्श है। यही कारण है कि इस विषय पर कोई भी मत अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। एक ओर ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सामाजिक और ऐतिहासिक वंचना की भरपाई के लिए जाति-आधारित आरक्षण अभी भी आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग यह तर्क देता है कि आज के भारत में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति होना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा है।

यदि किसी राष्ट्र की नीतियाँ योग्यता, प्रतिस्पर्धा और समान अवसरों की बजाय स्थायी पहचान-आधारित वर्गीकरण पर टिक जाएँ, तो वह राष्ट्र धीरे-धीरे अपनी प्रतिभा की पूरी क्षमता का उपयोग करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। समर्थकों का तर्क है कि



भी नीति निर्माण में महत्व दिया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण भी भारतीय संविधान और न्यायालयों में समय-समय पर हुए विमर्श का हिस्सा रहा है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच मूल प्रश्न यह है कि राष्ट्रहित में सर्वोत्तम संतुलन क्या हो सकता है। यदि किसी नीति का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आगे लाना है, तो यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सहायता वास्तविक रूप से सबसे अधिक जरूरतमंद तक पहुँचे। इस संदर्भ में आर्थिक मानकों को अधिक प्रभावी बनाने, लाभार्थियों की समय-समय पर समीक्षा करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों में व्यापक निवेश जैसे उपाय अवसर सुझाए जाते हैं। यह भी विचारणीय है कि यदि राजनीतिक दल आरक्षण के प्रश्न को चुनावी लाभ के लिए लगातार विस्तार देते रहें, तो समाज में नए-नए वर्गीय विभाजन उत्पन्न हो सकते हैं। जब प्रत्येक चुनाव में किसी नए समुदाय को आरक्षण का



फल, सूखे मेवे और पर्याप्त पानी इस आयु के लिए सर्वोत्तम हैं। युवावस्था में पढ़ाई, नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण लोग अवसर को नजर अंदाज कर देते हैं। नाश्ता छोड़ना, देर रात खाना और फास्ट फूड पर निर्भर रहना आम बात हो गई है। जबकि यही वह समय है जब स्वस्थ खान-पान की आदतें भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रखती हैं। साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियाँ, फल, कम वसा वाला



से हो, तब क्या केवल ध्वनि मत पर्याप्त लोकतांत्रिक संतुष्टि प्रदान करता है? और यदि विपक्ष मतदान का बहिष्कार करता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल बहुमत के आधार पर को नज़र पारित करना है, या उसे व्यापक राजनीतिक सहमति और सार्वजनिक विश्वास भी सुनिश्चित करना चाहिए? पेपर लीक केवल परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक विश्वास का प्रश्न। साथियों, सरकार का पक्ष यह रहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा को हराते हैं। अधिकारों के लिए कठोर कानून और त्वरित न्यायिक व्यवस्था आवश्यक है। यह तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठित परीक्षा अपराधों पर प्रभावी दंड, जांच और समयबद्ध सुनवाई की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन लोकतंत्र में कानून की कठोरता के साथ उसकी विश्ववसनीयता भी आवश्यक होती है। यदि कानून बनाने की प्रक्रिया में व्यापक चर्चा, संशोधनों पर विचार और विपक्ष की भागीदारी कम दिखाई दे, तो कानून की वैधानिकता तो बनी रहती है, किंतु उसके प्रति राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता

विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि समान अवसरों की नींव बचपन से रखी जाए, ताकि बाद की प्रतिस्पर्धा अधिक न्यायसंगत बने। आर्थिक सहायता-आधारित मॉडल के समर्थकों का मानना है कि राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी निर्धनता को कम करना है। यदि किसी गरीब परिवार का बच्चा केवल इसलिए पीछे रह जाए कि वह किसी आरक्षण श्रेणी में नहीं आता, तो यह व्यवस्था उसके साथ न्याय नहीं करती। उनके अनुसार छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क कौचिंग, शिक्षा ऋण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा और उद्यमिता सहायता जैसी योजनाएँ आर्थिक आधार पर अधिक व्यापक रूप से लागू की जा सकती हैं। हालाँकि, इस बहस का दूसरा पक्ष यह याद दिलाता है कि आर्थिक सहायता और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि कई बार पूरक भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले विस्तृत आँकड़ों, सामाजिक अनुसंधान, संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न समुदायों पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन आवश्यक है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय सामाजिक तनाव भी उत्पन्न कर सकते हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आरक्षण का प्रश्न समाज को बाँटने का माध्यम न बने। इसे न तो नफरत का हथियार बनाया जाए और न ही राजनीतिक लाभ का स्थायी साधन। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य स्थैय्य व्यवस्था विकसित करना होना चाहिए जिसमें कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल

अंततः प्रश्न केवल इतना नहीं है कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाए; प्रश्न यह है कि भारत ऐसा राष्ट्र कैसे बने जहाँ किसी नागरिक की सफलता उसके जन्म से नहीं, उसकी क्षमता, परिश्रम और उपलब्ध अवसरों से तय हो। इसी दिशा में नीति, राजनीति और समाज-तीनों को आत्मसंशोधन करना होगा। तभी सामाजिक न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय प्रगति के बीच स्थायी संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।

नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नमक, चीनी और तले हुए भोजन का सेवन सीमित करना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर की मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का कalcium कम हो जाता है और पाचन क्षमता भी घट सकती है। इस अवस्था में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12 और ओमेगा-3 फैटी एसिड का पर्याप्त सेवन अत्यंत आवश्यक है। दूध, पनीर, दालें, मछली, मेवे, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियाँ शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि बढ़ती उम्र में प्यास का एहसास कम हो सकता है। हालाँकि हर उम्र की अपनी अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। प्रतिदिन रंग-बिरंगे फल और सब्जियाँ खाएँ, साबुत अनाज को प्राथमिकता दें, अल्ट्राधक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, चीनी और नमक का सीमित उपयोग करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार मिलकर बेहतर स्वास्थ्य

प्रस्तावित करने, सरकार से स्पष्टीकरण मांगने और रिकॉर्डेड वोट के माध्यम से अपनी स्थिति दर्ज कराने का अवसर भी सीमित कर देता है इसलिए लोकतांत्रिक जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। सरकार को विपक्ष की बात सुनने और महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि विपक्ष को भी विरोध के साथ विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। लोकतंत्र में केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं; वैकल्पिक सुझाव देना, संशोधन प्रस्तुत करना और मतदान में अपनी स्थिति सटीकता से दर्ज कराना भी आवश्यक है। साथियों बात अगर हम ध्वनि मत क्या है और इसकी संवैधानिक संसदीय स्थिति क्या है? इसको समझने की करें तो ध्वनि मत भारतीय संसद की एक मान्य और लंबे समय से प्रचलित संसदीय प्रक्रिया है। इसमें अध्यक्ष या सभापति सदन से पृष्ठले हैं कि प्रस्ताव के पक्ष में कौन है और विरोध में कौन है। सदस्य हूँहाँह या हूँनहींह कहकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष ध्वनि की तीव्रता के आधार पर निर्णय देते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार हुआ या अस्वीकार। भारतीय संसदीय परंपरा में ध्वनि मत कोई असंवैधानिक या अवैध प्रक्रिया नहीं है; यह सामान्य संसदीय निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है लेकिन ध्वनि मत की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें प्रत्येक सांसद का व्यक्तिगत मतदान रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं होता। जनता यह नहीं जान पाती कि किस सांसद ने किसी विधेयक के पक्ष या विरोध में मतदान किया। यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति हो, तो नियमों के अनुसार वह विभाजन अर्थात् डिवीजन की मांग कर सकता है। विभाजन में मतों की गिनती

या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्पष्ट परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। यही से लोकतांत्रिक बहस शुरू होती है। ध्वनि मत सामान्य और गैर-विवादित मामलों में त्वरित निर्णय का प्रभावी माध्यम हो सकता है। लेकिन जब विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण हों, व्यापक जनहित से जुड़ा हो, राजनीतिक विवाद का विषय बना हो या विपक्ष उसकी धाराओं पर गंभीर आपत्ति कर रहा हो, तब रिकॉर्डेड मतदान लोकतांत्रिक पारदर्शिता को अधिक मजबूत कर सकता है। साथियों बात अगर हम क्या ध्वनि मत से विधेयक पारित होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है? इसको समझने की करें तो इस प्रश्न का उत्तर केवल हूँहाँह या हूँनहींह में नहीं दिया जा सकता। ध्वनि मत स्वयं लोकतंत्र-विरोधी नहीं है। संसद के नियमों में इसका स्थान है और अनेक मामलों में यह समय बचाने तथा सर्वसम्मति या स्पष्ट बहुमत वाले निर्णयों के लिए उपयोगी है। यदि सदन में पर्याप्त चर्चा हुई हो, सदस्य अपनी राय रख चुके हों और किसी सदस्य ने विभाजन की मांग न की हो, तो ध्वनि मत से निर्णय को संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत वैध माना जाता है लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ध्वनि मत विस्तृत बहस के विकल्प के रूप में दिखाई देने लगे। यदि किसी विधेयक पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, उसे संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया, विपक्ष की आपत्तियों पर गंभीर विचार नहीं हुआ और अंत में केवल ध्वनि मत से उसे पारित कर दिया गया, तो लोकतांत्रिक गुणवत्ता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार को निर्णय लेने का अधिकार देता है, किंतु बहस की आवश्यकता समाप्त नहीं करता।



‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान में साढ़े छह लाख से अधिक लोगों की भागीदारी

चार जुलाई से शुरू दूसरे चरण में अब तक 198 शिविर आयोजित, 20,808 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दूसरे चरण में अब तक 1 लाख 34 हजार 740 से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। इसके साथ ही अभियान के पहले और दूसरे चरण को मिलाकर कुल जनभागीदारी साढ़े छह लाख के पार पहुंच गई है। अभियान के तहत आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। चार जुलाई से शुरू



हुए इस विशेष अभियान के दौरान अब तक प्रदेशभर में 198 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। मानसून के बावजूद इन शिविरों में 1,34,740 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्राप्त 23,219 जनशिकायतों में से 20,808 का मौके पर ही निस्तारण किया गया,

जबकि 81,753 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया इन शिविरों में समाज कल्याण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, चिकित्सा उपकरण, कृषि उपकरण सहित अन्य आवश्यक सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर आयोजित शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में लोगों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। साथ ही पात्र लोगों के प्रमाणपत्र भी मौके पर बनाकर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके बीच पहुंचकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करे। इसी सोच के तहत गत दिसंबर माह में 45 दिनों का पहला

चरण आयोजित किया गया था, जिसमें 681 शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 5,33,452 नागरिकों ने भाग लिया और करीब 33 हजार जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस पहल को सुशासन की एक प्रभावी और सफल कार्यप्रणाली के रूप में भी सराहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के माध्यम से प्रशासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान कर रहा है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसके बिना जीवन का कोई भी सुख और सफलता अधूरी है: डा. ए. कन्नौजिया



वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। रविवार को विकास खंड सेमरियावां के दुधारा स्थित फैमिली फामेसी एंड क्लिनिक में दुर्गा मेडिकल सेंटर के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने लगभग दो सौ मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। सेमरियावां ब्लाक के फैमिली फामेसी एंड क्लिनिक दुधारा में दुर्गा मेडिकल सेंटर के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर

का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्गा मेडिकल सेंटर जगिना के चिकित्सक डा. ए. कन्नौजिया ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, क्योंकि इसके बिना जीवन का कोई भी सुख और सफलता अधूरी है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह तंदुरुस्त रहने की स्थिति है। जैसा कि कहा गया है—ह्रस्वहला सुख स्वस्थ शरीरह, स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति अपने जीवन के हर पल का आनंद उठा सकता है और अपने सभी सपने पूरे कर सकता

है। फैमिली फामेसी एंड क्लिनिक दुधारा के डीआरएक्स मोहम्मद फैजान ने कहा कि समय समय पर इस तरह का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होते रहना चाहिए। हमें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराते रहना चाहिए। स्वास्थ्य शिविर में डा. आर. कन्नौजिया, डा. निलोफर चौधरी, डा. अतिया सिराज, डा. साफिया सिराज की टीम ने लगभग दो सौ मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया।

कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड: फरार आरोपियों की तलाश में दबिश

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव नाला-ककड़ीपुर मार्ग पर कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह के निर्देश पर तीन टीमों का गठन किया गया है, जिनमें एसओजी, सर्विलांस टीम और थाना पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है तीन दिन पूर्व बागपत जनपद के गांव ककड़ीपुर निवासी 22 वर्षीय मोनु उर्फ गुल्लू की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले के खुलासे में पुलिस ने हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग को कारण बताया था पुलिस ने मृतक की प्रेमिका के पिता देशपाल और मुख्य आरोपी

कार्तिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में हत्याकांड के मुख्य आरोपी कार्तिक ने बताया था कि मृतक उसकी चचेरी बहन से फोन पर बातचीत करता था, जिसका वह विरोध करता था। कई बार समझाने के बावजूद जब मृतक नहीं माना तो उसने सुनियोजित तरीके से हत्या की साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, घटना में शामिल गांव भारसी निवासी अर्जुन और सत्यम अर्भी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीमों ने रविवार को कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका। थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस को जल्द ही दोनों आरोपियों को आला-कत्ल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जायगा।

थानाध्यक्ष दुधारा ने डायल-112/पीआरवी कर्मियों के साथ की बैठक, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। थाना दुधारा परिसर में थानाध्यक्ष अमित कुमार कुशवाहा ने थाना क्षेत्र में संचालित डायल-112/पीआरवी वाहनों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाना, जनता की शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना तथा पीआरवी कर्मियों को मानव बिना किसी विलंब के न्यूनतम समय में घटनास्थल पर पहुंचे तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।



उचित एवं न्यायसंगत कार्यवाही:- घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का गंभीरतापूर्वक आकलन करते हुए नियमानुसार निष्पक्ष एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। जनसामान्य के प्रति संवेदनशील व्यवहार:- शिकायतकर्ता एवं आमजन के साथ विनम्र, सम्मानजनक,

संवेदनशील एवं पेशेवर व्यवहार किया जाए, जिससे पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। सतर्कता एवं मुस्तैदी:- द्यूटी के दौरान सभी कर्मचारी पूर्ण सतर्कता के साथ निर्धारित वर्दी में रहें तथा वायरलेस सेट, टैबलेट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित रहें।

पारदर्शिता एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग:- प्रत्येक घटना की सही एवं तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार कर समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाए तथा आवश्यक फीडबैक भी उपलब्ध कराया जाए। बैठक के दौरान थानाध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा एवं सहायता पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूर्ण निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। बैठक के समापन पर उपस्थित समस्त पीआरवी कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, संवेदनशीलता एवं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पालन करने की शपथ दिलाई गई।

40 लाख की जमीन सौदे में धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, 24 लाख रुपये लेकर नहीं कराया बैनामा

कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त दबोचा

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मथारी निरीक्षक जयप्रकाश द्वे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह

कार्रवाई की। टीम में उपनिरीक्षक प्रभाष कुमार राय, कांस्टेबल मुकेश यादव तथा कांस्टेबल अमिर्तेज सिंह शामिल रहे। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 507/2026, धारा 338, 363(3), 340(2), 318(4), 319(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) से संबंधित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र गिरी पुत्र पशुपति नाथ गिरी, निवासी ग्राम बाँसपार, थाना गोडा, जनपद गोरखपुर को दुर्गा मंदिर, मगहर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 11 जून 2026 को वादिनी श्रीमती गुड्डी गुप्ता ने कोतवाली खलीलाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने भूमि बेचने के नाम पर 40 लाख रुपये में सौदा तय किया। इस दौरान

उन्होंने अग्रिम के रूप में 24 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें 16 लाख रुपये ऑनलाइन और 8 लाख रुपये नकद दिए गए। आरोप है कि धनराशि लेने के बाद भी आरोपियों ने जमीन का बैनामा नहीं कराया और विभिन्न बहाने बनाते हुए शेष रकम की मांग करते रहे। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि सौदे के दौरान कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की गई। जब पीड़िता ने अपनी धनराशि वापस मांगी तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जाने से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और अब मुख्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

ई-रिक्शा चालक से मारपीट का आरोप, स्टेशन मास्टर समेत दो के खिलाफ तहरीर

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के रेलवे स्टेशन पर सवारी लेने पहुंचे एक ई-रिक्शा चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने स्टेशन मास्टर समेत दो लोगों पर ई-रिक्शा के तार काटने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के सलेमपुर मार्ग निवासी मोबिन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। रविवार को वह रेलवे स्टेशन पर सवारी लेने के लिए पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान स्टेशन मास्टर और उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने पहले उसके ई-रिक्शा के तार काट दिए, जिसके बाद उसके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। विरोध करने



पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है। आरोपों की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रस्तावित पदयात्रा से पहले पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किए जाने का आरोप

वेलकम इंडिया संवाददाता

स्याना (बुलंदशहर)। विश्व सनातन हिन्दू फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि जातीय आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के विरोध और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर 1 अगस्त 2026 को प्रस्तावित शांतिपूर्ण जन-जागरूकता पदयात्रा को प्रशासन ने आयोजित नहीं होने दिया। संगठन के अनुसार, पदयात्रा की लिखित सूचना 27 जुलाई को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी मेरठ, डीजीपी उत्तर प्रदेश, उपजिलाधिकारी स्याना और क्षेत्राधिकारी स्याना सहित संबंधित अधिकारियों को दे दी गई थी। संगठन का दावा है कि प्रशासन को यह भी लिखित आश्वासन दिया गया था कि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में आयोजित किया जाएगा। विश्व सनातन हिन्दू फाउंडेशन का आरोप है



कि 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे से संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान सहित पवनेश कुमार, सोनू कुमार, पुलकित शर्मा और सचिन शर्मा को उनके आवासों पर पुलिस ने रोक दिया, जिसके कारण वे निर्धारित पदयात्रा में शामिल नहीं हो सके। संगठन ने सवाल उठाया है कि जब प्रशासन को पहले से सूचना दी जा चुकी थी और शांति बनाए रखने का आश्वासन भी दिया गया था, तो पदयात्रा से पहले आयोजकों को घरों में रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखना प्रत्येक नागरिक और संगठन का अधिकार है। विश्व सनातन हिन्दू फाउंडेशन ने प्रशासन से इस कार्रवाई का कानूनी आधार सार्वजनिक करने तथा पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही संगठन ने कहा कि वह आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को भविष्य में भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से उठाता रहेगा।

बाइक और ई-रिक्शा की आमने-सामने भिड़ंत, महिला घायल



वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के बाईपास मार्ग पर नेशनल इंटर कॉलेज के पास रविवार को बाइक और ई-रिक्शा की आमने-सामने की भिड़ंत में एक महिला घायल हो गई। हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल महिला को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कैराना निवासी शहजाद अपनी भाभी फरजाना के साथ बाइक से कस्बे में स्थित रिश्तेदारी

में आया था। लौटते समय जब बाइक सवार नेशनल इंटर कॉलेज के पास बाईपास मार्ग पर पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक ई-रिक्शा से उसकी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। समाचार लिखे जाने तक मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर नहीं दी गई थी।

पुरानी रजिश्त में स्कॉर्पियो से बाइक को मारी टक्कर

कांधला। कस्बे के मोहल्ला रायजादगान निवासी एक महिला ने पुरानी रजिश्त के चलते उसके पीत्र पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। महिला ने चार नामजद समेत अन्य लोगों पर बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो से जानबूझकर बाइक में टक्कर मारने और साजिश के तहत घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस से कार्रवाई में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रविवार को कस्बे के मोहल्ला रायजादगान निवासी श्यामों सेली सुभाष ने बताया कि उनके परिवार का जेट शोरा कश्यप और उसके परिवारजनों से लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। आरोप है कि पूर्व में भी उनके पुत्रों और पौत्रों पर कई बार हमले किए जा चुके हैं, जिनकी शिकायत पुलिस से की गई थी। महिला का आरोप है कि विगत शनिवार की रात करीब 10:30 बजे उसका पौत्र बंटी अपने छोटे भाई सन्नी और मित्र सावन के साथ दिल्ली बस स्टैंड स्थित दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था।

गोकशी व पुलिस पर फायरिंग के आरोपी पिता-पुत्र पर रासुका डेढ़ माह पहले सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस टीम पर बरसाई थीं गोलियां, तीनों पहले से जिला कारागार में निरुद्ध

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के मोहल्ला खेल में गोकशों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करने और गोकशी के मामले में गिरफ्तार आरोपी खलील कुरैशी तथा उसके दोनों पुत्र नदीम और नावेद के विरुद्ध पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका के तहत कार्रवाई की है। तीनों आरोपी पहले से ही मुजफ्फरनगर जिला कारागार में निरुद्ध हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गतिविधियां लोक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा थीं, इसलिए उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। करीब डेढ़ माह पूर्व पुलिस कस्बे के मोहल्ला खेल में गोकशों के सत्यापन और अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही थी। इसी दौरान

पुलिस टीम ने खलील कुरैशी के घर पर दबिश दी। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई से बौखलाए खलील ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें खलील कुरैशी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का सिपाही सुमित भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल खलील को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दोनों पुत्र नदीम और नावेद मौके से फरार हो गए। घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में गोवंश के अवशेष, गोकशों में प्रयुक्त धारदार हथियार, कटान के उपकरण तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी। बाद पुलिस ने नदीम और नावेद

को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों के न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वर्तमान में तीनों आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद हैं। रविवार को थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि गोकशी, पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों के जहनपद में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

दिव्यांग युवक और उसकी मां के साथ मारपीट, कार्रवाई की मांग

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। कस्बे के मोहल्ला खेल में एक अर्धविकसित युवक और उसकी मां के साथ भेज दिया गया। वर्तमान में तीनों आरोपी मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद हैं। रविवार को थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह ने बताया कि गोकशी, पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों के जहनपद में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।



भी मारपीट कर दी। आरोप है कि जाते समय आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने अपने दिव्यांग पुत्र के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में महिला को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।



